सभाध्यक्ष महोदय : जो किसान इस के नीचे आ गये हैं उनके हितों की रक्षा होनी चाहिये, उनके साथ न्याय हो, इस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, यह आप कह सकते हैं ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने यही कहा है ।

MR. SPEAKER: We shall now adjourn for lunch and meet again at 2.20.

12.23 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after for lunch till twenty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty-five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKERS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 14th December, 1981, will consist of:—

1. Discussion and voting on:

(a) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1981-82 and Demands for Excess Grants (Railways) for 1979-80.

(b) Supplementary Demands for Grants (General) for 1981-82 and Demands for Excess Grants (General) for 1979-80.

(c) Supplementary Demands for Grants for the State of Assam for 1981-82.

2. Discussion on the Resolution seeking approval of the Assam Notification relating to declaration of certain Services as Essential Services.

3. Discussion on the Resolution seeking approval for the continuance of the Proclamation issued by the President in relation to the State of Assam.

4. Discussion on the Resolution seeking approval of the Proclamation issued by the President in relation to State of Kerala.

5. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

6. Consideration and passing of the Plantation Labour (Amendment) Bill, 1981 as passed by Rajya Sabha.

7. Discussion under Rule 193 on the inadequacies in the electoral law in not providing a specific period for completion of a bye-election to Parliament at 4.00 p.m. on 14th December, 1981.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): There is a serious situation of unemployment in the country in which the energy of educated people is not being utilized properly. Greater industrial development is most necessary to eradicate present conditions of unemployment. Therefore, this matter should be discussed thoroughly in the House during next week.

Secondly, the problem of bonded labour still remains unsolved. There are lakhs of people who are working as bonded labour in UP, Bihar, Andhra Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana etc. This is a matter of grave concern. Therefore, a discussion should be allowed on this subject during the next week.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I request the inclusion of the following matter in the list of business commencing from the next week:

"Scarcity and maldistribution of cement."

Cement is an essential commodity and also a controlled item. State-wise allotment have always remained inadequate to meet the requirement of the State. There are reports that distribution of this scarce item is not proper and the distribution system requires to be improved. Attention has been focussed on various allegations about corruptions, malpractices in the distribution, particularly in the State of Maharashtra, through the press and platforms.

A detailed discussion on the cement policy including production, import and distribution, is necessary.

I hope you would agree on this.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यवाही के लिये निम्नलिखित दो बातें सम्मिलित कराना चाहता हूं :

(1) देश में कपड़ा उद्योग की स्थिति विचारणीय बन गयी है । इस उद्योग में काम करने वाले लाखों मजदूरों और कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित है । मध्य प्रदेश की दो प्रमुख कपड़ा मिलें विनोद और विमल 8 नवम्बर से लगातार बन्द हैं । उक्त मिलों की रिलीफ अन्डर टेकिंग के तहत घोषित प्रावधानों की छूट मिली हुई है । किन्तु मिलें बन्द हैं । इन मिलों को इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड रेगूलेशन ऐक्ट, 1951 के तहत तत्काल अधिग्रहीत कर हजारों मजदूरों की जीविका को बचाया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार राष्ट्रीय वस्त्र नियम (एन०टी०सी०) के मारकेटिंग डिवीजन जिसमें इस निगम द्वारा उत्पादित 3 प्रतिशत कपड़े का ही व्यापार किया जाता है, कार्यरत कर्मचारियों का वेतन काफी कम है । इन कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । इनके वेतन में वृद्धि करने का शीघ्र निर्णय लेना चाहिये ।

अतएव कपड़ा उद्योग की सुस्थिति, बन्द मिलों को चालू करने तथा इनमें काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का विषय चर्चा में सम्मिलित किया जाये ।

(2) किसान को उसके कृषि उत्पादनों का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है । शक्कर कारखाने किसान को गन्ने का उपयुक्त मूल्य नहीं दे रहे हैं । कई शक्कर कारखाने अभी चालू नहीं हुए हैं । किसान गन्ने के खेतों में गेहूं की लेट वैरायटी को बोना चाहता है । उसे गन्ना सस्ते मूल्य पर बेचने को बाध्य किया जा रहा है । मध्य प्रदेश में जावरा और माहिदपुर रोड के शक्कर कारखानों ने किसानों और कर्मचारियों का लाखों रुपयों का बकाया भुगतान नहीं किया है ।

अतएव मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों को उसके द्वारा उत्पादित गन्ने का उपयुक्त समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित करने के लिये उपर्युक्त विषय को सम्मिलित किया जाये ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यवाही के लिये निम्न दो बातें सम्मिलित कराना चाहता हूं :

(1) आगरा जिले और उसके समीपवर्ती मैनपुरी, इटावा, बांदा, फतेहपुर,

[श्री सत्यनारायण जटिया]

कानपुर, एटा आदि जिलों में व मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिलों में पुलिस मल्लाहों का उत्पीड़न कर रही है और उनके घरों को लूट रही है। उनके झूठे चालान कर रही है, उनकी स्त्रियों को बेइज्जत कर रही है। अनेक समाचार-पत्रों में व सरकार के पास अनेक शिकायतें आई हैं परन्तु अब तक उन मल्लाहों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है बल्कि पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न बराबर बढ़ रहा है। तुरन्त ही इस उत्पीड़न को रोकने की व्यवस्था होनी आवश्यक है।

(2) देश में बराबर पुलिस आतंक व दमन बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर लोगों के जान-माल को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। पुलिस के मनमाने अत्याचारों व कानून को अपने हाथ में लेने के मामले बराबर बढ़ते जा रहे हैं और लोग पुलिस व्यवस्था से भयभीत होने लगे हैं। इसलिये पुलिस व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है। पुलिस के कार्य को तीन भागों में विभाजित करना जरूरी हो गया है। प्रथम सूचना दर्ज करने का कार्य मुन्सिफ व तहसीलदारों के हवाले कर दिया जाए और इन्वेस्टीगेशन सैकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेटों को सौंप दी जाए। शेष कार्य पुलिस के हाथ में रहे तभी पुलिस व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly): Sir, on several occasions in the past the Central Government has been subject to severe criticism that it was ignoring and denying the rightful claim and representations of State in many matters.

In the recently reconstituted Telephone Advisory Committee of Calcutta nominations have been made and persons have been chosen in a manner without observing the well-established norms in this regard. Although the ruling Left Front in West Bengal accounts for more than 250 in a House of 294, no legislator belonging to any of the constituents of the Left Front has been given a berth in the Calcutta Telephone Advisory Committee. Nor does any representative of the ruling Left Front or any of its constituents find place in the new body. It is, therefore requested that all parties in the Legislature should be given due representation in this body according to their strength.

Another such matter has been seen in the formation of the Advisory Committee....

MR. DEPUTY SPEAKER: Which item do you want to be included?

PROF. RUP CHAND PAL: Another such matter has been seen in the formation of the Advisory Committee attached to AIR Calcutta. The Minister of Information and Broadcasting, who is sitting here, had fully agreed in clear terms that the names of persons for this Advisory Committee would be decided in consultation with the State Government. Accordingly, a panel of names was suggested by the West Bengal Minister of Information and Cultural Affairs. But not a single name from the West Bengal Minister's panel found a place in the Committee that has been formed now.

I would request that a discussion on the constitution of these Bodies should be incorporated in the List of Business for the next week.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): This is not correct.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा): उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 1980 को बजट की

कृषि मंत्रालय की मांगों पर माननीय कृषि मंत्री, राव वीरेन्द्र सिंह, ने लोक सभा में घोषणा की थी कि किसानों के हित में लैंड एक्वीजीशन एक्ट में संशोधन किया जाएगा । माननीया प्रधान मंत्री ने 16 फरवरी, 1981 को किसान रैली के सम्मुख घोषणा की थी कि उपरोक्त एक्ट में संशोधन कराया जाएगा । मेरे दो पत्रों के उत्तर में माननीया प्रधान मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, उनमें भी ये आश्वासन दिए हैं ।

राज्य सभा में माननीय कृषि मंत्री कह चुके हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी घोषणा की है । मेरे मौखिक अनुरोध पर माननीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री सहयोग करेंगे, तो संशोधन इसी सत्र में आ जाएगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी सहयोग करने का मौखिक आश्वासन दिया है, किन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यक्रम में उसका उल्लेख नहीं किया है ।

मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण बिल को कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित कर लिया जाए, ताकि लगभग 90 वर्ष पुराने एक्ट के कारण किसानों के साथ होने वाला अन्याय समाप्त हो जाए ।

MR. DEPUTY SPEAKER: Only what you have given in writing will go on record.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का मैं आग्रह करता हूं ।

चालू मौसम में गन्ने का मूल्य 13 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है, जो निश्चित रूप से किसानों के लिए अलाभकर है । आज किसानों के ऊपर राजस्व की दर, डीजल, खाद, बिजली, कृषि-यंत्रों की कीमत, मजदूरी की दर में 25 से 45 प्रतिशत तक बढ़ने का भार है । किन्तु गन्ने का मूल्य है वही 13 रुपये, जो 1977 में निर्धारित हुआ था । सरकार ने अधिक दर में विदेशों से आयात कर भारतीय किसानों को पैदावार का मूल्य कम रख कर भारतीय किसानों का अहित किया है । आज सरकारी वेतन-भोगियों के वेतन 1977 की तुलना में 60 प्रतिशत बढ़ गए है । अतः गन्ने का मूल्य 1977 की दर पर रखने का कोई औचित्य नहीं है । उसका लाभकर मूल्य निश्चित किया जाना चाहिए ।

मेरा दूसरा सुझाव मंडल आयोग का प्रतिवेदन संसद् के सभा-पटल पर रखने के बारे में है । मंडल आयोग का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने का आश्वासन सरकार ने संसद् के पिछले सत्र में दिया था, किन्तु उसे अभी तक नहीं रखा गया है । इस प्रतिवेदन से देश की 50 प्रतिशत जनता जुड़ी है । इसे इस सत्र में पटल पर रखा जाए ।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I wanted to mention four points. But the hon. Speaker has permitted me to mention only two points. Therefore, I will not mention the points of law and order situation and the collapse of fly-over. I will mention only two points.

I request that the following two points may kindly be included in the next week's business.

Several irregularities in the financial management of the Punjab and Sind Bank have come to light.

The Reserve Btnk of India has already been investigating into these

[Shri Bapusaheb Paruleker]

irregularities since long but they have yet to come out with results. The issue is of great importance from the point of view of investers and depositors. There is need for a discussion on the affairs of the Punjab and Sind Bank.

The second point which I would like to mention is that the question of Indians working in Dubai has again drawn the attention of the Indian public. A young Indian woman was raped in Dubai. This news has been published in *Daccan Chronicle* Hyderabad on 8-12-81. This should be discussed on the overall question of Indians working in the Gulf countries.

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, a large number of West Bengal Bills pending with the Central Government resulting in non-implementation of various important legislation on land reforms, industrial law education and other subjects need to be expedited.

Secondly, the office of the Railway Service Commission was opened at Calcutta long back to recruit class III employees for the Eastern, the South Eastern and the Chittaranjan Locomotive Works and since then it has been discharging its duties satisfactorily.

A major part of the Eastern Railway is spread over West Bengal and Bihar. The former Railway Minister, late Shri L. N. Mishra shifted a portion of the Commission's office to Muzaffarpur in Bihar in order to provide employment opportunities to unemployed youth of Bihar in the Eastern Railway. That office is still functioning. The remaining portion of the said office continued to function from Calcutta to cater to the need of unemployed youth from West Bengal and the Eastern region in the matter of job opportunities.

Now, it is reported that the present Railway Minister has decided to shift the remaining portion of the said Commission's office from Calcutta to Danapur (Bihar) which will jeopardise the job opportunities of unemployed youth of the Eastern region of the country.

This smacks of regionalism. Otherwise there is no logic to locate two Railway Commission offices in one State. The only reason behind this discriminatory measure appears to be to deprive the youth of the Eastern region outside Bihar of their job opportunities and to my opinion this is against the basic tenets of the Indian Constitution. Therefore, I demand that this House should direct the Railway Minister to drop the reported shifting of the said office which amounts to misuse of the office for regional purposes.

This item should be included in the next week's business.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I am thankful to hon. Members for the points raised by them. I will go through the proceedings and if I think proper, I will bring them to the notice of the Business Advisory Committee.

14.43 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-THIRD REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Twenty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th December, 1981."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Twenty-third Report of the